

of affluence and power then, there is no use of getting rid of Art. 314. I hope Mr. Chavan will consider this aspect of the matter and tell us what he has to say about this.

Before I close, please permit me to recite a couplet, particularly for Shri Chavan's benefit to understand the ICS officers. It is in very simple Urdu :

“तालिबे हुस्न तो सैकड़ों हैं मगर,
दर्दगम का लतबगार कोई नहीं,
पीने वालों में बैठे हैं कुछ गैर भी,
एक कतरा न देना इन्हें साकिया,
ये मयखवार हैं वक्त के भार हैं,
इनमें तेरा परिस्तार कोई नहीं।

18.46 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
FORTY-SEVENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND SHIPPING AND
TRANSPORT (SHRI RAGHU RAM-
AIAH): Sir, I beg to present the Forty
Seventh Report of the Business Advisory
Committee.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of Article 314)

by Shri Madhu Limaye

श्री सरजू पाण्डेय (राजीपुर): समापति महो-
दय, जो बिल सदन में आया है मैं उसका समर्थन
करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कई माननीय
सदस्यों ने तरह तरह के तर्क दिये हैं लेकिन
हिन्दुस्तान की आजादी के बाईस वर्ष के बाद भी
मैं नहीं समझता कि हमारे संविधान में जो व्यव-
स्था की गई है और आई०सी०एस० अफसरों
को जो सुविधायें दी गई हैं उनको देने का कारण
क्या है।

बाईस वर्ष की आजादी के दौरान हम ने
देखा है कि देश में एक चेतना आई है, समाज
में एक नई चेतना पैदा हुई है और आज कई

प्रश्न हमारे सामने आये हैं। कई बार इस
संविधान को बदलने का अवसर भी आया है।
हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है और जिन
बुनियादी अधिकारों को हम ने अपने संविधान
में रक्खा है उनके सम्बन्ध में देश के बहुत से
लोगों ने, बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने मांग की
है कि संविधान में से सम्पत्ति के अधिकार को
हटा दिया जाये। यह आई० सी० एस० हमारे
संविधान में कलंक है। यहाँ पर नौकरशाही ने
देश की जनता को छूटने, उसको दबाने और
बरबाद करने का काम किया है। उनमें हमारे
आई० सी० एस० आफिसर भी हैं। इन आई०
सी० एस० आफिसरों ने आज तक देश की जनता
के साथ बेईमानी की है। हम कानून बनाते हैं,
लेकिन लागू करने वाले अधिकारी उसका अर्थ
कुछ और लगाते हैं। नतीजा यह होता है कि
समाज में गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं।

कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमारे देश
में आई० सी० एस० आफिसरों को सुविधायें देने
की क्या जरूरत है जबकि हम देश में समाज-
वादी समाज की रचना की बात करते हैं ?
खासतौर से कुछ लोगों को इस तरह की सुवि-
धायें देना और उसका संविधान में बना रहना
अच्छी बात नहीं है। प्रक्सर राजाओं के बारे में
प्रश्न उठता है। हम लोगों ने कई बार मांग की
है, और वह प्रश्न आने वाला भी है, कि उनकी
सुविधायें खत्म की जायें। अब वह वक्त भी
आ गया है कि हम अपने संविधान में संशोधन
करें और जो आई० सी० एस० अफसर हमारे
देश में बैठे हुए हैं उनकी सुविधाओं को हटा दें,
उनको समाप्त करें।

जो लोग हमारे देश की आजादी के लिए
लड़ें, जिनकी कुर्बानियों से आज हम लोग इस
सदन में बैठे हुए हैं, आज वह नहीं हैं, और
अगर हैं भी तो राज काज में हिस्सा नहीं ले
रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन जिन
लोगों ने हमको कुचला था, जो हम पर जुल्म